**सिविल अपील**

**न्यायमूर्ति शमशेर बहादुर और आरएस नरूला के समक्ष,**

**गुलाब राय, ---अपीलकर्ता**

**बनाम**

**भारत संघ और अन्य,----- उत्तरदाता।**

**1961 की नियमित प्रथम अपील संख्या 235**

**14 मार्च, 1969**

*मजदूरी संदाय अधिनियम (1936 का IV) - धारा 15 और 22 - सरकार के अधीन कामगार को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर सेवा से बर्खास्त किया जाना - उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि रद्द कर दी गई - बर्खास्तगी का आदेश सरकार द्वारा वापस नहीं लिया गया - ऐसा कामगार - क्या अधिनियम के तहत प्राधिकरण के समक्ष मजदूरी का दावा कर सकता है - सिविल में ऐसी मजदूरी के लिए मुकदमा न्यायालय - क्या धारा 22 (डी) के तहत प्रतिबंधित है।*

*सिविल प्रक्रिया संहिता ( 1908 का ५ ) - वादपत्र में एक विशेष पैराग्राफ के लिखित बयान में "ज्ञान की कमी के कारण इनकार" की दलील - ऐसी दलील - क्या प्रतिवादी पर दायित्व तय करने के लिए स्वीकार करने के बराबर है।*

अभिनिर्धारित किया की कोई बर्खास्त कामगार सेवा में पुन: बहाली पर अपने नियोक्ता के खिलाफ बकाया मजदूरी के लिए मुकदमा दायर करता है, तो यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण केवल यह नहीं है कि मुकदमा दायर किया जा सकता है या नहीं, या केवल यह नहीं है कि वाद की तारीख को मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 की धारा 15 के तहत प्राधिकरण को आवेदन किया जा सकता है या नहीं। लेकिन यह भी कि क्या मुकदमा से पहले ऐसा आवेदन किया जा सकता था। किसी मुकदमे पर विचार करने के लिए सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र कर्मचारी की पसंद पर निर्भर नहीं करेगा कि उसे अधिनियम के तहत प्राधिकरण पर लागू करना चाहिए या नहीं। सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को केवल तभी खारिज किया जाता है जब मुकदमा दायर होने से पहले किसी भी समय प्राधिकरण को आवेदन किया जा सकता है। लेकिन यह वहां लागू होता है जहां पुन: बहाली का आदेश वास्तव में सरकार द्वारा ही पारित किया जाता है और पिछली अवधि की मजदूरी के बारे में विवाद उत्पन्न होता है। जहां, हालांकि, किसी कर्मचारी की दोषसिद्धि पर बर्खास्तगी का आदेश पारित किया जाता है और उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को रद्द कर दिया जाता है, तो कर्मचारी अधिनियम के तहत प्राधिकरण के समक्ष मजदूरी का दावा नहीं कर सकता है, जब तक कि दोषसिद्धि को रद्द नहीं किया जाता है। बर्खास्तगी का आदेश एक पूरी तरह से वैध आदेश है जब इसे पारित किया जाता है। हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा कर्मचारी को बरी किए जाने के परिणामस्वरूप वह आदेश गलत हो जाता है, कर्मचारी संभवत: उस अवधि के लिए मजदूरी नहीं मांग सकता है जिसके दौरान उसे बर्खास्त कर दिया जाता है जब तक कि नियोक्ता द्वारा बर्खास्तगी का आदेश वापस नहीं लिया जाता है या सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा शून्य या अप्रभावी नहीं ठहराया जाता है। चूंकि कर्मचारी अधिनियम की धारा 15 (2) के तहत किसी भी समय मुकदमा शुरू होने से पहले आवेदन नहीं कर सकता है, इसलिए वह उस अवधि के लिए मजदूरी के किसी भी हिस्से का दावा नहीं कर सकता है, जब वह बर्खास्त हो जाता है, इसलिए अधिनियम की धारा 22 (डी) के तहत मुकदमा प्रतिबंधित नहीं है।

**(पैरा 9 और 10)**

अभिनिर्धारित है की वाद-पत्र में एक विशेष पैराग्राफ के लिखित बयान में प्रतिवादी द्वारा "ज्ञान की कमी के कारण इनकार" करना उस पैराग्राफ में कथित तथ्यों के अस्तित्व से इनकार करने के समान नहीं हो सकता है, लेकिन यह एक स्वीकारोक्ति के बराबर नहीं है जो प्रतिवादी को उस आधार पर दायित्व के साथ तय कर सकता है, खासकर जब वादी वाद के उस पैराग्राफ में निहित आरोपों को साबित करने में विफल रहता है।

श्री ओंकार नाथ, उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, रोहतक की अदालत के दिनांक 10 अक्टूबर, 1960 के आदेश से नियमित प्रथम अपील, जिसमें वादी के वाद को खारिज कर दिया गया था।

**अपीलकर्ता के लिए आत्मा राम वकील।**

**एच.एस. गुजराल और बीरिंदर सिंह, प्रतिवादी नंबर १ के लिए वकील।**
**राम रंग, वकील, प्रतिवादी नंबर २ के लिए।**

## निर्णय

**न्यायमूर्ति नरूला,** - यह असफल वादी द्वारा नियमित प्रथम अपील श्री ओंकार नाथ, अधीनस्थ न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, रोहतक के 10 अक्टूबर, 1960 के फैसले और डिक्री के खिलाफ निर्देशित की जाती है, जिसके तहत अपीलकर्ता द्वारा 25,099:25 रुपये की वसूली के लिए दायर मुकदमे को जुर्माने के साथ खारिज कर दिया गया था।

(2) इस अपील के फैसले के लिए प्रासंगिक तथ्य विवाद में नहीं हैं। गुलाब राय, वादी-अपीलकर्ता, जिन्हें मैं इस फैसले में वादी कहूंगा, भारत संघ के रेलवे विभाग की स्थायी सेवा में थे, और 17 नवंबर, 1952 को रोहतक जिले के बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन में हेड बुकिंग क्लर्क के रूप में स्थानांतरित कर दिए गए थे। 14 मार्च, 1953 को उन्हें कथित तौर पर 1,00,000 रुपये की राशि स्वीकार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।11 उस दिन एक ज्वाला पार्षद से भ्रष्ट और गैर-कानूनी तरीकों से और लोक सेवक के रूप में अपने पद का दुरुपयोग करके। भारतीय रेलवे स्थापना संहिता, खंड-II के परिशिष्ट XXXI-R की धारा I H(1), जो वादी की सेवा शर्तों को नियंत्रित करती है, नीचे दी गई है: –

> "एक रेलवे कर्मचारी जिसके खिलाफ ऋण के लिए या आपराधिक आरोप में उसकी गिरफ्तारी के लिए कार्यवाही की गई है, उसे किसी भी अवधि के लिए निलंबित माना जाना चाहिए, जिसके दौरान उसे हिरासत में रखा गया है या कारावास से गुजर रहा है और ऐसी अवधि के लिए नियम 2043-आर (मौलिक नियम एस 3) में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार दिए जाने वाले किसी भी निर्वाह भत्ते के अलावा कोई वेतन और भत्ता लेने की अनुमति नहीं है। जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती। ऐसी अवधि के लिए उसके भत्तों का समायोजन उसके बाद मामले की परिस्थितियों के अनुसार किया जाना चाहिए, पूरी राशि केवल अधिकारी को दोष से बरी होने की स्थिति में दी जा रही है या (यदि उसके खिलाफ की गई कार्यवाही ऋण के लिए उसकी गिरफ्तारी के लिए थी) यह साबित होने के बाद कि अधिकारी की देयता उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों से उत्पन्न हुई है।

उत्तर रेलवे के मंडल कार्मिक अधिकारी को जैसे ही उपरोक्त परिस्थितियों में वादी की गिरफ्तारी की सूचना मिली, उन्होंने स्टेशन मास्टर, बहादुरगढ़ को दिनांक 14 मार्च, 1953 को टेलीग्राम, प्रदर्शनी डीडब्ल्यू 2/13 जारी किया, जिसमें इस प्रकार लिखा था: –

> 'बीसी (बुकिंग क्लर्क) गुलाब राय को तत्काल निलंबित कर दिया जाए. वह आधा वेतन और महंगाई भत्ता लेंगे जो निर्वाह भत्ते के रूप में स्वीकार्य है।

(3) वादी को उचित समय पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 (1) (डी) के तहत इस आरोप पर मुकदमे के लिए रखा गया था कि उसने उक्त अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत दंडनीय अपराध किया था। यद्यपि वादी ने मूल रूप से दावा किया था कि उनकी जन्म तिथि 30 दिसंबर, 1903 थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट का यह निष्कर्ष कि उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 1 जुलाई, 1899 होने की उनकी जन्मतिथि के आधार पर निर्धारित की जानी थी, हमारे सामने विवादित नहीं है। इसलिए वादी ने 30 जून, 1954 को 55 वर्ष की आयु प्राप्त की। भारतीय रेल स्थापना

संहिता, खंड-II का नियम 2046 (2) (क) जो बुकिंग क्लर्क जैसे रेल मंत्रालयसेवक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु निर्धारित करता है, निम्नलिखित शर्तों में है -

> "एक मंत्रिस्तरीय सेवक, जो उप-खंड (बी) द्वारा शासित नहीं है, को 55 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन आमतौर पर सेवा में बनाए रखा जाना चाहिए, अगर वह 60 वर्ष की आयु तक कुशल रहता है। उसे उस उम्र के बाद बहुत विशेष परिस्थितियों को छोड़कर नहीं रखा जाना चाहिए, जिसे लिखित रूप में और सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ दर्ज किया जाना चाहिए।

(4) यह दोनों पक्षों का स्वीकार किया गया मामला है कि वादी का मामला नियम 2046 के उप-नियम (2) के खंड (ए) द्वारा शासित था, और आगे यह कि किसी भी स्तर पर किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, जिसमें वादी को 55 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने की आवश्यकता हो। श्री आई. एम. लाई, विशेष न्यायाधीश, अंबाला के दिनांक 30 अगस्त, 1954 (प्रदर्शनी पृष्ठ 6) के आदेश से, वादी को तकनीकी आधार पर उपर्युक्त आपराधिक मामले से मुक्त कर दिया गया था कि उसके अभियोजन की मंजूरी, जो मंडल वाणिज्यिक अधीक्षक, उत्तर रेलवे द्वारा दी गई थी, एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं थी - मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक से उसके अभियोजन के लिए उचित मंजूरी, 24 सितंबर, 1954 को एक सक्षम प्राधिकारी (प्रदर्शनी पृष्ठ 70) प्राप्त किया गया था। उक्त मंजूरी के आधार पर, वादी को 25 मार्च, 1955 को अंबाला के विशेष न्यायाधीश की अदालत में फिर से मुकदमे के लिए भेजा गया था। श्री हंस राज खन्ना, विशेष न्यायाधीश, अंबाला (अब दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना) ने 27 मई, 1957 के अपने फैसले में वादी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (2) के तहत दंडनीय धारा 5 (1) (डी) के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया, और उक्त प्रावधान के तहत वादी को दोषी ठहराया। उसे दो महीने के कठोर कारावास और 100 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जब वादी की दोषसिद्धि रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, अंबाला शहर से प्राप्त हुई, तो मंडल अधीक्षक, दिल्ली ने 18 जून, 1957 को निम्नलिखित प्रभाव के लिए आदेश प्रदर्शन डीडब्ल्यू 3/1 पारित किया: –

> "दोषी ठहराए जाने के मद्देनजर कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है।"

संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) के परंतुक (ए) के कारण, वादी ने किसी भी जांच या किसी अन्य औपचारिकता की आवश्यकता के बिना सेवा से संक्षिप्त बर्खास्तगी अर्जित की थी। संभागीय अधीक्षक के उपर्युक्त आदेश के आधार पर संचार, प्रदर्शनी डी-डब्ल्यू। 20 जून, 1957 की तारीख वाले 2/16 को डिवीजनल कार्मिक अधिकारी को भेजा गया था, जिसमें उन्हें वादी को उसकी दोषसिद्धि के मद्देनजर सेवा से बर्खास्त करने की आवश्यकता थी। पत्र प्रदर्शनी डीडब्ल्यू 2/16 की प्राप्ति पर, संभागीय कार्मिक अधिकारी ने 21 जून, 1957 को औपचारिक आदेश प्रदर्शनी डीडब्ल्यू 2/15 पारित किया, जो वादी को इन शब्दों में संबोधित किया गया था: -

> "आपको सूचित किया जाता है कि डी.एस., दिल्ली (मंडल अधीक्षक, दिल्ली) द्वारा पारित आदेशों के अनुसार, आपको निम्नलिखित दंड दिया गया है: –
>
> न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के परिणामस्वरूप आपको 23 जून, 1957 (एफ-एन-) से सेवा से बर्खास्त किया जाता है।"

प्रदर्श डीडब्ल्यू 2/8 उसी आदेश की एक और प्रति है- इसके बाद औपचारिक आदेश प्रदर्शनी डी-डब्ल्यू। दिनांक 12 नवम्बर, 1957 की अधिसूचना सं 2/14, उन परिलब्धियों के संबंध में, जिनके लिए वादी अपने निलंबन की अवधि का हकदार था, निम्नलिखित शर्तों में पारित किया गया था:-

> "वह (गुलाब राय वादी) निर्वाह भत्ते के रूप में पहले से प्राप्त राशि से अधिक कुछ नहीं लेंगे. निलंबन की अवधि को एसयूएस के रूप में माना जाएगा, यानी, सेवा के लिए योग्य नहीं है।"

(5) 4 मार्च, 1958 को न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश (एस. बी. कपूर, जे. जैसा कि वह थे) के निर्णय और आदेश से, अंबाला के विशेष न्यायाधीश द्वारा उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ वादी की अपील को स्वीकार कर लिया गया था, और उन्हें संदेह का लाभ दिए जाने पर बरी कर दिया गया था। वादी के बरी होने का नतीजा

यह हुआ कि सेवा से उसकी बर्खास्तगी के आदेश का आधार गायब हो गया। इसके बावजूद वादी को बहाल नहीं किया गया। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत 10 नवंबर, 1958 को सामान्य नोटिस देने के बाद, वादी ने 3 मार्च, 1959 को ट्रायल कोर्ट में आवेदन दायर किया, जिसमें प्रतिवादी नंबर 1 से 15,554-25 रुपये की वसूली के लिए मुकदमा करने की अनुमति मांगी गई। अर्थात, 14 मार्च, 1953 से और 31 मार्च, 1959 को समाप्त, जिसमें उक्त अवधि के दौरान उनके द्वारा अर्जित वेतन वृद्धि की राशि, वादी से वसूल किए गए मकान किराए की वापसी और उस अवधि के लिए घर के किराए के लिए दावा शामिल है, जिसके लिए उसे इस तरह के भत्ते का भुगतान नहीं किया गया था (जिस अवधि के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा वादी को नियमों के तहत आवश्यक कोई किराया-मुक्त आवास नहीं दिया गया था) इस प्रकार देय कुल राशि से समायोजित करने के बाद, उस अवधि के दौरान उसे भुगतान की गई निर्वाह भत्ते की राशि। वादी ने रेलवे प्रशासन का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत संघ से और प्रतिवादी संख्या 2 और 3 (कल्याण सरूप, सहायक स्टेशन मास्टर और जमना दास, संबंधित समय में बहादुरगढ़ के स्टेशन मास्टर) से दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए नुकसान के रूप में 9,545 रुपये की एक और राशि का दावा किया। वादी को फॉर्मा कंगाली में मुकदमा करने के लिए छुट्टी दी गई थी। मुकदमे को रेलवे प्रशासन के साथ-साथ प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा भी चुनौती दी गई थी। पक्षकारों की दलीलों से, ट्रायल कोर्ट ने निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए: -

1. क्या प्रतिवादी 2 और 3 ने वादी को झूठे आपराधिक मामले में फंसाने के उद्देश्य से वाद के पैराग्राफ 66 में लगाए गए आरोप के अनुसार साजिश रची?
2. क्या प्रतिवादी संख्या 2 और 3 ने 14 मार्च, 1953 को अन्य लोगों के साथ बिना किसी उचित और संभावित कारण के अपने डिजाइन को आगे बढ़ाने के लिए और दुर्भावना से प्रेरित होकर वादी को झूठे आपराधिक मामले में झूठा फंसाया?
3. मुद्दे संख्या 1 और 2 के प्रमाण के मामले में क्या प्रतिवादी 2 और 3 नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं जैसा कि वादी द्वारा दावा किया गया है?
4. प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के खिलाफ वादी कितनी क्षतिपूर्ति का हकदार है?
5. क्या मुकदमा समय के अनुसार प्रतिबंधित है?
6. क्या मजदूरी भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुकदमा प्रतिबंधित है?
7. क्या प्रतिवादी संख्या 1 को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत दिया गया नोटिस अमान्य है?
8. क्या वादी की बर्खास्तगी का आदेश वाद में बताए गए आधार पर शून्य है?
9. वादी की सेवानिवृत्ति की तारीख क्या है और इसका क्या प्रभाव है?
10. वादी के पैराग्राफ 14 और 17 में बताए गए वेतन और क्षति की बकाया राशि के लिए वादी हकदार है?
11. क्या प्रतिवादी नंबर 2 विशेष लागत का हकदार है?
12. मदद।

10 अक्टूबर, 1960 के अपने फैसले से, ट्रायल कोर्ट ने मुद्दों संख्या 1 से 4 पर पाया कि प्रतिवादी नंबर 2 और 3 को वादी को झूठे आपराधिक मामले में फंसाने के उद्देश्य से साजिश में प्रवेश करने के लिए साबित नहीं किया गया था, कि वादी का अभियोजन बिना किसी उचित और संभावित कारण के नहीं था। और किसी भी दुर्भावना से प्रेरित नहीं था, और इसलिए, वादी कथित दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के कारण किसी भी नुकसान का हकदार नहीं था। अपनी परिलब्धियों की बकाया राशि के लिए भारत संघ के खिलाफ वादी के दावे से संबंधित अन्य मुद्दों पर यह माना गया कि उसके मुकदमे को न तो समय द्वारा और न ही मजदूरी भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के तहत रोका गया था, कि प्रतिवादी नंबर 1 पर वादी द्वारा नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत एक वैध नोटिस दिया गया था। यह कि वादी को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश अपील में बरी होने पर स्वत: रद्द हो जाता है, कि वादी की सेवानिवृत्ति की तारीख 30 जून, 1954 थी (उसकी अनुमानित जन्म तिथि 1 जुलाई, 1899 पाई गई थी), कि 55 वर्ष की आयु में वादी की सेवानिवृत्ति की सामान्य तारीख को उच्च न्यायालय द्वारा बरी किए जाने की तारीख तक बढ़ा दिया गया था; लेकिन वादी किसी भी

राहत का हकदार नहीं था क्योंकि वह 14 मार्च, 1953 से उसके बरी होने की तारीख तक निलंबित था और उसके निलंबन के आदेश की वैधता को मुकदमे में चुनौती नहीं दी गई थी।

(6) ट्रायल कोर्ट के डिक्री से संतुष्ट नहीं होने पर, वादी इस अदालत में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 44 नियम 1 के तहत फॉर्म कंगाली में अपील करने की अनुमति के लिए आया था। उनका आवेदन खारिज कर दिया गया था, लेकिन उन्हें अदालत की फीस में कमी को पूरा करने की अनुमति दी गई थी। उस स्तर पर उन्होंने दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए 7,600 रुपये की सीमा तक क्षतिपूर्ति के लिए अपना दावा छोड़ दिया और अपने उक्त दावे (जो मूल रूप से 9,545 रुपये के लिए था) को केवल 1,945 रुपये तक सीमित कर दिया और अपने वेतन और भत्तों के बकाया के कारण केवल 17,499.25 रुपये (15,545.25 रुपये) की राशि पर अदालत-शुल्क के प्रयोजनों के लिए अपनी अपील का मूल्यांकन किया। आदि, और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए नुकसान के रूप में 1,945 रुपये)।

(7) अपील की सुनवाई के दौरान दीवान आत्मा राम ने दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के अपने दावे के समर्थन में वादी के नेतृत्व में सबूतों के माध्यम से हमें ले लिया और कुछ हद तक आधे-अधूरे मन से तर्क दिया कि मुद्दा संख्या 1 और 2 पर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष उलट दिए जाने योग्य थे। यह स्पष्ट रूप से बताए बिना कि वह नुकसान के कारण 1,945 रुपये के लिए अपने ग्राहक के दावे पर दबाव नहीं डाल रहा था, उसने वास्तव में सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उस दावे को छोड़ दिया।

i. तथ्य यह है कि वादी को प्रतिवादी नंबर 2 या प्रतिवादी नंबर 3 की किसी भी रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा मुकदमा नहीं चलाया गया था;

ii. तथ्य यह है कि ट्रायल कोर्ट जिसे वादी के गवाहों को देखने का लाभ मिला था, जिन्हें कथित साजिश को साबित करने के लिए पेश किया गया था, ने अच्छे कारणों से कहा था कि उनके बयान विश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं;

iii. तथ्य यह है कि यह विश्वास करना आसान नहीं है कि सतर्कता अधिकारी प्रतिवादी 2 और 3 के साथ एक निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाने की साजिश रच रहा था;

iv. तथ्य यह है कि कथित साजिश का एकमात्र सबूत P.Ws की मौखिक गवाही थी, जिसने दावा किया था कि वह प्रतिवादी 2 और 3 और पुलिस अधिकारियों के बीच कथित बातचीत पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और यह सर्वविदित है कि "पीपिंग टॉम्स" के सबूतों को शायद ही कभी किसी ठोस सबूत के साथ माना जाता है; और

v. आगे तथ्य यह है कि वादी को विशेष न्यायाधीश द्वारा दोषी ठहराया गया था, लेकिन अंततः इस न्यायालय द्वारा केवल संदेह का लाभ प्राप्त करने पर बरी कर दिया गया था।

इसलिए, हमें मुद्दे संख्या 1 और 2 पर ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्षों की पुष्टि करने और दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए नुकसान के लिए वादी के दावे को खारिज करने में कोई संकोच नहीं है।

(8) वादी के वकील ने तब प्रस्तुत किया कि हम मानते हैं कि प्रतिवादी 2 और 3 के खिलाफ नुकसान के दावे की पुष्टि नहीं हुई है, भारत संघ के खिलाफ उस खाते पर दावा की गई राशि के लिए एक डिक्री पारित की जानी चाहिए क्योंकि वादी के पैराग्राफ 5 और 6 में निम्नलिखित कथनों को भारत संघ द्वारा सही माना गया है:

"5. प्रतिवादी 2 और 3 के साथ-साथ बहादुरगढ़ में शुरू से ही काम कर रहे अन्य रेलवे कर्मचारियों को आवेदक के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया गया था और उन्होंने वहां उसकी पोस्टिंग का जोरदार विरोध किया था। आवेदक एक ईमानदार और सीधा आदमी है और वह कर्मचारियों की ओर से कर्तव्य की किसी भी लापरवाही को इंगित करता था और इससे उस पर पूरे स्टाफ की नाराजगी होती थी।

6. उनकी उपस्थिति से छुटकारा पाने के लिए, प्रतिवादी 2 और 3 ने स्टाफ के अन्य सदस्यों के साथ श्री अब्बास, इंस्पेक्टर स्पेशल पुलिस इस्टैब्लिशमेंट, दिल्ली और पुलिस उपाधीक्षक श्री रोशन लाई के साथ मिलकर एक नापाक साजिश रची, जिसका उद्देश्य उन्हें झूठे आपराधिक मामले में फंसाना था। इस डिजाइन को आगे बढ़ाने के लिए, 14 मार्च, 1953 को बिना किसी उचित और संभावित कारण के और

दुर्भावना से प्रेरित होकर आवेदक को झूठे और तुच्छ मामले में फंसा दिया। बाद में उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम द्वितीय 1947 की धारा 5 (2) के तहत गिरफ्तार किया गया था, और उन्हें खुद को रिहा करने के लिए 3,000 रुपये की जमानत राशि देनी पड़ी थी। आवेदक को प्रतिवादी नंबर 1 के आदेश के तहत 14 मार्च, 1953 से निलंबित कर दिया गया था।"

भारत संघ ने अपने लिखित वक्तव्य के संबंधित पैराग्राफों में जो कहा था, वह यह था -

"5. पैराग्राफ 5 को ज्ञान की कमी के कारण अस्वीकार कर दिया गया है।

6. पैरा 6 में इस हद तक स्वीकार किया गया है कि वादी को 14 मार्च, 1953 से डी.एस.पी./एस.आर.ई. से एक संदेश प्राप्त होने पर निलंबित कर दिया गया था। बाकी को ज्ञान के अभाव में मना कर दिया जाता है।"

वकील चाहते थे कि हम नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 5 में निर्धारित सिद्धांतों के आवेदन पर यह कहें जैसा कि *जहुरी साह और अन्य बनाम द्वारिका प्रसाद झुनझुनवाला और अन्य*[1] में व्याख्या की गई है।, भारत संघ द्वारा 'ज्ञान की कमी के लिए इनकार' वादी के पैराग्राफ 5 और 6 में कथित तथ्यों के अस्तित्व से इनकार करने के समान नहीं है- हम यह मानने में असमर्थ हैं कि 'ज्ञान की कमी के लिए इनकार' इस तरह की स्वीकारोक्ति के बराबर है कि केवल उस कारण से संबंधित प्रतिवादी को दोषी ठहराया जाए, खासकर जब हमने तथ्यों को पकड़ लिया है। यह मामला है कि वादी वादी के पैराग्राफ 5 और 6 में उसके द्वारा लगाए गए आरोपों को साबित करने में विफल रहा है।

(9) भारत संघ के खिलाफ वेतन आदि के बकाया के लिए वादी के दावे के संबंध में दीवान आत्मा राम द्वारा इस मामले में वास्तविक तर्कों को संबोधित किया गया था। वादी के विद्वान वकील द्वारा सरकार के खिलाफ अपने दावे के गुण-दोष पर दी गई प्रस्तुतियों से निपटने से पहले, मुद्दा संख्या 6 पर रेलवे प्रशासन के विद्वान वकील श्री हरबंस सिंह गुजराल की दलीलों का निपटारा करना आवश्यक है। श्री गुजराल ने आग्रह किया कि वाद के पैरा 14 में वर्णित वादी के पूरे दावे पर विचार करने या निर्णय लेने से सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को मजदूरी भुगतान अधिनियम (1936 का 4) की धारा 22 (डी) (जिसे बाद में मजदूरी अधिनियम कहा जाता है) द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है, श्री गुजराल ने प्रस्तुत किया कि वेतन के बकाया के अलावा जो निश्चित रूप से मजदूरी है। वेतन वृद्धि के रूप में वादी द्वारा दावा की गई राशि भी एक वेतन है जैसा कि मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा प्रबंध निदेशक, *टीएसटी कंपनी लिमिटेड बनाम आर पेरुमल नायडू और अन्य*[2] में कहा गया है। उस मामले में यह माना गया था कि नियोक्ता और कामगार के बीच अनुबंध के तहत देय वेतन वृद्धि मजदूरी अधिनियम की धारा 15 के अर्थ के भीतर मजदूरी होगी। इसी तरह, वकील ने *अनंत राम और अन्य बनाम जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर और अन्य*[3] मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले के आधार पर प्रस्तुत किया। *पुरुषोत्तम एच. हुडे और अन्य बनाम वी. बी. पोतदार*[4], मामले में सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप के आधिकारिक फैसले के आधार पर। मजदूरी भुगतान अधिनियम के तहत नियुक्त प्राधिकरण और अन्य, कि ग्रेच्युटी जो एक साधन के तहत देय है, मजदूरी अधिनियम के अर्थ के भीतर "मजदूरी" शब्द की परिभाषा के अंतर्गत भी आती है। मद्रास उच्च न्यायालय के खंडपीठ के फैसले के अधिकार पर श्री गुजराल द्वारा मजदूरी अधिनियम के अर्थ "मजदूरी" अभिव्यक्ति में शामिल करने के लिए निलंबन अवधि के लिए देय राशि भी मांगी गई है। *पी दोराइकन्नू बनाम प्रॉपरिएटर, होटल सेवॉय, मद्रास*[5] में इसलिए, यह तर्क दिया गया था कि वादी के दावे का गठन करने वाली सभी मदें जैसा कि उसके वाद के पैराग्राफ 14 में निहित है, कथित अवैध हिरासत के लिए "मजदूरी" शब्द के अंतर्गत आती है, जिसका दावा मजदूरी अधिनियम की धारा 15 के तहत किया जाता है- तब यह प्रस्तुत किया गया था कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप ने एक दावे के संबंध में दीवानी मुकदमे की रोक का सवाल छोड़ दिया था। *बॉम्बे*

---

1 A.I.R. 1967 S.C. 109.
2 A.I.R. 1958 Mad. 25
3 A.I.R. 1956 Raj. 145.
4 A.I.R. 1966 S.C. 856.
5 A.I.R. 1966 Mad. 201.

*गैस कं. लिमिटेड बनाम गोपाल भिवा और अन्य,*[6] में खुले मजदूरी अधिनियम के तहत दायर किया गया है। यह *केवलराम घाना श्यामदास और अन्य बनाम राम मनोहरदास कल्याणदास*[7] मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक पूर्ण पीठ द्वारा आयोजित किया गया है । और हाल ही में भारत संघ बनाम मोहन सिंह चौधरी[8] मामले में इस न्यायालय के एक असूचित निर्णय में कहा कि मजदूरी अधिनियम की धारा 15 के तहत पसंद किए जा सकने वाले दावे के संबंध में मुकदमा मजदूरी अधिनियम की धारा 22 के खंड (डी) के तहत निषिद्ध है, भले ही उक्त अधिनियम के तहत दावा करने की सीमा पहले ही समाप्त हो गई हो। मजदूरी अधिनियम की धारा 22 के प्रासंगिक भाग में कहा गया है: –

"कोई भी अदालत मजदूरी की वसूली या मजदूरी से किसी भी कटौती के लिए किसी भी मुकदमे पर विचार नहीं करेगी, जहां तक दावा की गई राशि है-

(क) * * * ** *
(ख) * * * * ** * **

* * * ** **

(ग) *

(घ) धारा १५ के तहत आवेदन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।"

धारा 15 में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान है कि अधिनियम के अधीन प्राधिकारी उस क्षेत्र में नियोजित अथवा भुगतान किए गए व्यक्तियों की मजदूरी से कटौती अथवा भुगतान में विलंब से उत्पन्न होने वाले सभी दावों की सुनवाई और निर्णय ले सकता है, जिस पर प्राधिकरण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। धारा 15 की उप-धारा (2) में कहा गया है कि उस उप-धारा के तहत एक आवेदन केवल उस तारीख से बारह महीने के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है जिस तारीख को मजदूरी से कटौती की गई थी या उस तारीख से जिस तारीख को मजदूरी का भुगतान किया जाना था, जैसा कि मामला हो, बशर्ते कि उस संबंध में प्राधिकरण द्वारा समय बढ़ाया जा सकता है यदि वह संतुष्ट है कि दावेदार के पास पर्याप्त कारण नहीं था। निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन करना- केवलराम घाना श्यामदास और, अन्य (सुप्रा), (5) के मामले में , बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने कहा कि एक सिविल कोर्ट को मजदूरी अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) द्वारा निर्धारित सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद मजदूरी की वसूली के लिए अपने नियोक्ता के खिलाफ एक कर्मचारी द्वारा दायर मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है। उस अधिनियम के तहत नियुक्त किया गया है या यदि प्राधिकरण ने इस तरह के आवेदन करने में देरी को माफ करने से इनकार कर दिया है। धारा 22 के खंड (डी) में इस्तेमाल की गई "धारा 15 के तहत एक आवेदन द्वारा पुनर्प्राप्त किया जा सकता था" शब्द को बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ द्वारा व्याख्या किया गया था, जिसका अर्थ था "धारा 15 के तहत दावा की गई राशि की वसूली के लिए आवेदन किया जा सकता था" यह माना गया था कि मुकदमा झूठ बोल सकता है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण केवल यह नहीं है कि वाद की तारीख पर आवेदन किया जा सकता है या नहीं। धारा 15 के तहत प्राधिकरण के लिए, लेकिन यह भी कि क्या मुकदमा की संस्था के समक्ष ऐसा आवेदन किया जा सकता था। उस आधार पर यह फैसला सुनाया गया था कि किसी मुकदमे पर विचार करने के लिए सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र कर्मचारी की पसंद पर निर्भर नहीं करेगा कि उसे मजदूरी अधिनियम के तहत प्राधिकरण पर लागू होना चाहिए या नहीं, और यह कि सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाएगा यदि मुकदमा दायर होने से पहले किसी भी समय प्राधिकरण को आवेदन किया जा सकता था। मोहन सिंह चौधरी के मामले *(पूर्वोक्त) (6)* में, इस न्यायालय की एक खंडपीठ *(*संधावलिया, जे. और मैं*)* ने *रिसाल सिंह बनाम भारत संघ और अन्य*[9], मामले में फालशॉ, जे. (जैसा कि वह तब थे) के एकल पीठ के फैसले को मंजूरी दे दी। *भागवत राय बनाम भारत संघ और अन्य* [10]नागपुर उच्च न्यायालय के खंडपीठ के फैसले के बारे में यह माना कि

6 A I.R. 1964 S.C. 752.
7 A I.R. 1965 Bom. 185.
8 F.A. 94 of 1958 decided on 20th August, 1968.
9 1958 P.L.R. 227.
10 A.I.R. 1958 Nag. 136.

जहां किसी कर्मचारी को सेवा से हटाए जाने के बाद, लेकिन बाद में बहाल कर दिया जाता है, तो इसे या तो काटे गए वेतन या मजदूरी के रूप में माना जा सकता है जिसके बारे में भुगतान में देरी हुई है, और यह कि ऐसे मामलों में, मजदूरी अधिनियम के तहत प्राधिकरण के पास कामगार के दावे पर निर्णय लेने का अधिकार है। मोहन सिंह चौधरी ने वास्तव में मजदूरी अधिनियम की धारा 15 के तहत दावा किया था, जिसे उस अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकारी द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि धारा 15 के तहत आवेदन उस धारा की उप-धारा (2) के तहत निर्धारित सीमा की अवधि से परे किया गया था। इसलिए, मोहन सिंह चौधरी के पक्ष में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के खिलाफ भारत संघ की अपील को हमारे द्वारा अनुमति दी गई थी, और उनके मुकदमे को नियमित प्रथम अपील में मजदूरी अधिनियम की धारा **22 (**डी**)** द्वारा प्रतिबंधित मानते हुए खारिज कर दिया गया था।यह सभी चार पर है, और उसी का पालन करते हुए हमें मुद्दे संख्या **6** पर ट्रायल कोर्ट के फैसले को उलट देना चाहिए, और अन्य मुद्दों पर विचार किए बिना वादी के मुकदमे को खारिज करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखना चाहिए। रेलवे प्रशासन के विद्वान वकील ने हमें यह आश्वासन दिया कि यदि हम इस आधार पर अपील को खारिज कर देते हैं, तो रेलवे प्रशासन **14** मार्च, **1953** से **4** मार्च, **1958** की अवधि के लिए देय परिलब्धियों के लिए वादी के दावे पर विचार करेगा, अर्थात, निलंबन के आदेश की तारीख से लेकर उच्च न्यायालय द्वारा उसे बरी किए जाने की तारीख तक, विभागीय रूप से, जैसा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि मुद्दा संख्या **8** पर ट्रायल कोर्ट का निर्णय ठोस और सही है।

(10) इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, हम श्री गुजराल की इस बात से सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि केवलराम घाना श्यामदास और अन्य *(7)* और मोहन सिंह चौधरी *(8)* के मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून इस मामले के तथ्यों पर कोई लागू होता है। उन दोनों मामलों में बहाली का आदेश वास्तव में सरकार द्वारा पारित किया गया था और उसके बाद पिछली अवधि के लिए मजदूरी के संबंध में विवाद उत्पन्न हुए थे। रिसाल सिंह के मामले **(9)** के साथ-साथ मोहन सिंह चौधरी **(8)** के मामले में हमारे फैसले में संदर्भित अन्य मामलों में भी यही स्थिति थी। हालांकि, वर्तमान मामले में, वादी की बर्खास्तगी का आदेश जो **18/21** जून, **1957** को सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया था, जो पारित होने पर पूरी तरह से वैध आदेश था, सरकार द्वारा कभी वापस नहीं लिया गया था। उच्च न्यायालय द्वारा वादी को बरी किए जाने के परिणामस्वरूप वह आदेश चाहे कितना भी गलत क्यों न हो गया हो, वादी संभवतः उस अवधि की मजदूरी नहीं मांग सकता था जिसके दौरान वह तब तक बर्खास्त रहा था जब तक कि उसकी बर्खास्तगी का आदेश नियोक्ता द्वारा वापस नहीं ले लिया जाता था या सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा शून्य या अप्रभावी नहीं ठहराया जाता था। यही कारण है कि वादी ने अपनी याचिका के पैराग्राफ **12** में विशेष रूप से दावा किया कि अंबाला के विशेष न्यायाधीश द्वारा **27** मई, **1957** को उनकी दोषसिद्धि के आधार पर सेवा से उनकी बर्खास्तगी का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें बरी किए जाने के बाद स्वचालित रूप से गिर गया था, और वादी बहाल होने और पूर्ण वेतन और महंगाई भत्ते सहित अन्य परिलब्धियां प्राप्त करने का हकदार था। आदि, नियमों के तहत उसे अनुमेय - परिलब्धियों के कारण धन डिक्री के लिए दावा वादी द्वारा उठाए गए उपरोक्त रुख पर आधारित था। इस संबंध में वादी के दावे को भारत संघ द्वारा खारिज कर दिया गया था। इस विवाद के कारण मुद्दा संख्या **8** तैयार किया गया जिसे पहले ही ऊपर पुन: प्रस्तुत किया जा चुका है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वादी द्वारा अपने वाद पत्र के पैरा **12** में किए गए दावे और भारत संघ के लिखित बयान के संबंधित पैराग्राफ में खंडन और मुद्दे संख्या **8** की विषय-वस्तु बनाने पर संभवतः मजदूरी अधिनियम की धारा **15** के तहत प्राधिकरण द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सकता था। उनकी बर्खास्तगी का आदेश या तो प्रभाव में नहीं था या शून्य हो गया था, मजदूरी के दावे की नींव नहीं रखी जा सकती थी। केरल उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने *जे. मालबी डी'क्रूज़ और अन्य बनाम त्रावणकोर मिनरल्स लिमिटेड के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी और अन्य* "के मामले में फैसला सुनाया । ने कहा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा **25**-एफ के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए वास्तव में छंटनी किए गए कामगार को अभी भी सेवा में नहीं माना जा सकता है ताकि वह अपने रोजगार की समाप्ति के बावजूद मजदूरी अर्जित करने का हकदार हो, जब तक कि उसकी छंटनी का आदेश उचित कार्यवाही में रद्द नहीं कर दिया जाता है। उस निर्णय का अनुपात, जिसके साथ हम सम्मानपूर्वक सहमत हैं,

---

11 AJJR. 1968 Kerala 121.

एक कामगार के मामले पर लागू होता है जो उस अवधि के लिए मजदूरी की वसूली के लिए मजदूरी अधिनियम के तहत प्राधिकरण से संपर्क करना चाहता है, जिस अवधि के दौरान उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, पहले बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किए बिना। इस मामले की परिस्थितियों में, इसलिए, हम मानते हैं कि वादी किसी भी समय वर्तमान मुकदमे में दावा की गई राशि के किसी भी हिस्से का दावा करते हुए मजदूरी अधिनियम की धारा **15 (2)** के तहत आवेदन नहीं कर सकता था, जिस मुकदमे से वर्तमान अपील उत्पन्न हुई है- हम श्री गुजराल से सहमत हैं कि जिस आधार पर ट्रायल कोर्ट ने संघ के खिलाफ मुद्दा संख्या **6** तय किया है। भारत पूरी तरह से गलत और गलत है। विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने कहा कि मुकदमे में दावा मजदूरी अधिनियम के तहत प्राधिकरण के समक्ष नहीं लाया जा सकता था क्योंकि इसका हिस्सा दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए क्षतिपूर्ति के लिए है। दावे के दो आइटम अलग-अलग और आसानी से विच्छेदयोग्य हैं। दो दावों के लिए कार्रवाई के कारण पूरी तरह से अलग हैं। जबकि परिलब्धियों का दावा केवल भारत संघ के खिलाफ किया जाता है जो मुकदमे में प्रतिवादी नंबर **1** था, दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए नुकसान के दावे को सभी तीन प्रतिवादियों के खिलाफ प्राथमिकता दी गई है। श्री गुजराल का तर्क है कि उपर्युक्त दोनों दावों के संबंध में संयुक्त मुकदमा, जैसा कि गठित किया गया है, बहुविधता के कारण खराब था, अर्थात, कार्रवाई के कारणों के गलत होने के कारण, और इस संबंध में *गोकल चंद बनाम ख्वाजा अली शाह और अन्य*[12] में पंजाब के मुख्य न्यायालय के खंडपीठ के फैसले पर निर्भर करता है। और *पुलवर्ती वेंकन्ना बनाम जुपुडी सरय्या और अन्य*[13]मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले पर और एक अन्य मामले में। वकील प्रस्तुत करता है कि वह अब इस स्तर पर यह दावा नहीं करता है कि वादी-अपीलकर्ता के मुकदमे को बहुविधता के कारण खारिज कर दिया जाना चाहिए, लेकिन प्रस्तुत करता है कि उपरोक्त दो निर्णयों के अधिकार पर, यह माना जाना चाहिए कि कार्रवाई के दो कारण बिल्कुल अलग और स्पष्ट रूप से विच्छेदयोग्य थे, और यदि कार्रवाई के उन कारणों में से एक पर आधारित दावा मजदूरी अधिनियम की धारा **22 (**डी**)** के तहत प्रतिबंधित था, इसे सिविल कोर्ट में केवल इसलिए प्राथमिकता देने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी क्योंकि मजदूरी अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई के पूरी तरह से अलग और विशिष्ट कारण पर दावा विचार योग्य नहीं था। हम इस संबंध में श्री गुजराल से सहमत हैं, लेकिन फिर भी मुद्दा संख्या **6** पर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष को उलटने में असमर्थ हैं क्योंकि हम पहले ही ऊपर कह चुके हैं कि वादी वर्तमान मुकदमा दायर करने से पहले किसी भी समय मजदूरी अधिनियम की धारा **15 (1)** के तहत अपनी मजदूरी की राशि का दावा नहीं कर सकता था क्योंकि सरकार द्वारा उसकी बहाली का कोई आदेश पारित नहीं किया गया था और वह ऐसा नहीं कर सकता था। सीधे मजदूरी का दावा किया जब वह अभी भी बर्खास्तगी के आदेश के अधीन था, चाहे आदेश कितना भी अवैध क्यों न हो।

(11) वादी के दावे के गुण-दोष पर दिवान आत्मा राम की दलीलों को नोटिस करने के लिए आगे बढ़ने के लिए आधार अब स्पष्ट है, जिसे सुरक्षित रूप से निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: –

(a) **14** मार्च**, 1953** से **2** जनवरी**, 1956** की अवधि के लिए परिलब्धियों की शेष राशि **(**वादी द्वारा प्राप्त निर्वाह भत्ते के लिए क्रेडिट देने के बाद**)** के संबंध में दावा**;**

(b) **3** जनवरी**, 1956** से **4** मार्च की अवधि के लिए परिलब्धियों के लिए दावा। **1958;** और

(c) **5** मार्च**, 1958** से **31** मार्च की अवधि के संबंध में दावा। **1959.**

वादी को **14** मार्च**, 1953** से **4** मार्च**, 1958** की अवधि के लिए परिलब्धियों का अधिकार समान होगा, लेकिन मैंने इसे दो अलग-अलग भागों **(**ए और बी**)** में विभाजित किया है क्योंकि मुकदमा शुरू होने की तारीख से तीन साल और दो महीने से अधिक की अवधि से संबंधित भाग **(**ए**)** द्वारा कवर किए गए दावे से संबंधित हैं। यदि वादी के दावे का वह हिस्सा जो ऊपर भाग **(**ए**)** द्वारा कवर किया गया है, समय के भीतर माना जाता है, तो वादी के दावे के भाग **(**ए**)** और भाग **(**बी**)** के बीच कोई अन्य अंतर नहीं होगा। भाग **(**सी**)** द्वारा कवर की गई अवधि के संबंध में दावा पूरी तरह

12 32 P.R. 1890.
13 4 I.C. 1097 (2).

से अलग स्तर पर है, और केवल तभी सफल होने का हकदार होगा जब हम मानते हैं कि मामले की परिस्थितियों में, वादी को 4 मार्च, 1958 के बाद सेवा में बने रहने के लिए माना गया था।

(12) मैं पहले 14 मार्च, 1953 से 4 मार्च, 1958 की अवधि के लिए परिलब्धियों के वादी के दावे पर विचार करूंगा, जो सीमा के प्रश्न के अधीन है। श्री गुजराल के तर्क में इस आशय का कोई बल नहीं है कि 12 नवंबर, 1957 (पहले से उद्धृत) के आदेश प्रदर्शनी डीडब्ल्यू 2/14 ने इस अवधि के लिए वादी के दावे को समाप्त कर दिया क्योंकि इसमें कहा गया था कि वादी को निर्वाह भत्ते के रूप में पहले से प्राप्त राशि से अधिक कुछ भी नहीं मिलेगा। चूंकि यह सक्षम प्राधिकारी को तय करने का अधिकार है कि वादी को निलंबन की अवधि के लिए क्या परिलब्धियां प्राप्त करने की अनुमति दी जाएगी। भारतीय रेलवे स्थापना संहिता, खंड II (पहले से उद्धृत) के परिशिष्ट XXXI-R की धारा III (1) में कहा गया है कि निलंबन की अवधि के लिए रेलवे सेवक के भत्ते का समायोजन मामले की परिस्थितियों के अनुसार किया जाना चाहिए, लेकिन इस बात पर जोर दिया गया है कि "पूरी राशि केवल अधिकारी को दोष से बरी होने की स्थिति में दी जा रही है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यदि किसी रेलवे कर्मचारी को आपराधिक आरोप में उसकी गिरफ्तारी के कारण निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन बाद में आपराधिक न्यायालय द्वारा बरी कर दिया जाता है, तो वह अपने निर्वाह के लिए पहले से भुगतान की गई राशि से कम अपने पूर्ण भत्ते का हकदार होगा। किसी भी घटना में, आदेश डीडब्ल्यू 2/14, जो 12 नवंबर, 1957 को पारित किया गया था, केवल वादी की दोषसिद्धि पर बर्खास्तगी के परिणामस्वरूप था और वादी के बरी होते ही प्रभावी हो गया। इसलिए, यदि वादी विचाराधीन अवधि के लिए कुछ भी करने का हकदार था, तो वह अपनी पूर्ण परिलब्धियों का हकदार होगा, जैसे कि उसे कभी भी निलंबित नहीं किया गया था। श्री गुजराल ने स्वीकार किया कि रेलवे प्रशासन द्वारा वादी के वेतन आदि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होने के बारे में रेलवे प्रशासन द्वारा किया गया बचाव क्योंकि उसे सम्मानजनक रूप से बरी नहीं किया गया था, बल्कि केवल संदेह का लाभ दिए जाने के कारण बरी कर दिया गया था, *जगमोहन लाई बनाम पंजाब राज्य और अन्य*[14] मामले में इस न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए सही नहीं है । इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा *केके जग्गिया बनाम पंजाब राज्य,*[15] मामले में यह निर्णय पहले ही दिया जा चुका है। बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करने और सरकारी कर्मचारी की बहाली के बाद यह निलंबन गलत हो जाता है। श्री गुजराल ने प्रस्तुत किया कि केके जग्गिया के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून वादी के मामले पर लागू नहीं होता है क्योंकि बहाली का कोई आदेश उनके पक्ष में पारित नहीं किया गया था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वादी की सेवा से बर्खास्तगी का आदेश पूरी तरह से और विशेष रूप से उसकी दोषसिद्धि पर पारित किया गया था, और बर्खास्तगी के उक्त आदेश को इस न्यायालय द्वारा वादी के बरी होने पर प्रभाव नहीं माना जाता है, वादी तत्काल बहाली का हकदार था और हमें उन परिलब्धियों के सवाल पर फैसला करना होगा जिनके लिए वादी इस आधार पर हकदार है कि उसे माना जाता है। नियम 2046 के उप-नियम (4) के तहत अपनी विस्तारित सेवा की समाप्ति पर 4 मार्च, 1958 को सेवा में बहाल किया गया, जिसके लिए वादी के दावे के भाग (सी) से निपटने के दौरान संदर्भ दिया जाएगा। हमारी राय है कि यद्यपि ट्रायल कोर्ट इस आशय के अपने निष्कर्ष में सही था कि वादी को 4 मार्च, 1958 को सेवानिवृत्त माना गया था, लेकिन उसने यह कहते हुए गलती की कि वह किसी भी राहत का हकदार नहीं था। यह मानने के बावजूद कि वादी की सेवानिवृत्ति की तारीख भारतीय रेलवे स्थापना संहिता के नियम 2046 के उपनियम (4) के संचालन द्वारा 4 मार्च, 1958 तक बढ़ा दी गई थी, ट्रायल कोर्ट ने वादी को 4 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए उसकी परिलब्धियों के संबंध में कोई राहत देने से इनकार कर दिया। 1958, दो आधारों पर, अर्थात्:-

(1) यह कि वर्तमान मुकदमे में वादी द्वारा निलंबन के आदेश को चुनौती नहीं दी गई थी और इस प्रकार निलंबन आदेश की वैधता के पक्ष और विपक्ष में जाना न्यायालय का काम नहीं था ; और

(2) वादी किसी भी वेतन का हकदार नहीं था क्योंकि उसे उन नियमों के तहत निलंबित कर दिया गया था जिसके अधीन वह अपनी सेवा के अनुबंध के एक हिस्से के रूप में था और एक सरकारी

14 A.I.R. 1967 Pb. 422
15 965 P.L.R. 1092.

कर्मचारी निलंबन की अवधि के दौरान उसी दर पर वेतन का हकदार नहीं है, जिस पर वह उसी दर पर इसका हकदार होता यदि उसे निलंबित नहीं किया गया होता।

केके जग्गिया के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्णय के अधिकार के संबंध में हम पहले ही कह चुके हैं कि बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त करने और सरकारी कर्मचारी की बहाली पर निलंबन का आदेश गलत हो जाता है। एक बार जब वादी द्वारा बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती दी गई और उसकी चुनौती को उचित पाया गया, तो उसके निलंबन का आदेश स्वचालित रूप से बर्खास्तगी के आदेश के साथ गायब हो गया। दूसरे आधार के लिए जिस पर वादी का दावा खारिज कर दिया गया था, विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश ने *मंडल अधीक्षक, उत्तर रेलवे, दिल्ली डिवीजन बनाम मुकंद लाई*[16] में इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया। उस मामले में, यह माना गया था कि मजदूरी भुगतान अधिनियम के तहत एक प्राधिकरण नियोक्ता को उस अवधि के संबंध में किसी कामगार की मजदूरी की पूरी राशि का भुगतान करने का आदेश देने के लिए सक्षम नहीं है, जिसके दौरान वह निलंबित था, यदि उसे उसके सेवा नियमों के अनुसार निलंबित कर दिया गया है। मुकंद लाल मामले में निर्धारित कानून का इस मामले पर कोई प्रभाव नहीं है क्योंकि सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का दायरा मजदूरी भुगतान अधिनियम के तहत एक प्राधिकरण की तुलना में बहुत व्यापक है। मैं निश्चित रूप से ऐसे मामलों की परिकल्पना कर सकता हूं जिनमें निलंबन के आदेश को किसी भी तरह से प्रभावित किए बिना बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया जाएगा। उस प्रकार के मामले में, निलंबन का आदेश बर्खास्तगी के आदेश के अमान्य होने की घोषणा से भी बच सकता है; लेकिन इस मामले में, निलंबन और बर्खास्तगी का आदेश दोनों एक आपराधिक आरोप पर वादी की गिरफ्तारी और दोषसिद्धि पर आधारित थे और वादी के आपराधिक आरोप से बरी होने से दोनों का स्वत: अंत हो गया। दोनों आधार जिन पर ट्रायल कोर्ट ने इस संबंध में वादी के दावे की अनुमति देने से इनकार कर दिया, इसलिए कानून में गलत थे। इन परिस्थितियों में, हम यह कहेंगे कि परिसीमा के प्रश्न के अधीन, वादी **14** मार्च, **1953** से **4** मार्च, **1958** की अवधि के लिए उसके द्वारा दावा की गई राशि का हकदार है, क्योंकि श्री गुजराल अपने वाद के पैरा ग्राफ **14** में वादी द्वारा की गई गणना में किसी भी त्रुटि को इंगित करने में असमर्थ थे।

(13) जहां तक परिसीमा का प्रश्न है, क्या *माधव लक्षनियन वैकुंथे बनाम मैसूर राज्य*[17] उच्चतम न्यायालय के उनके लॉर्डशिप द्वारा आधिकारिक रूप से इसका समाधान किया गया है? परिसीमा अधिनियम, **1903** की पहली अनुसूची का अनुच्छेद **102,** वेतन के बकाया के लिए एक मुकदमे पर लागू होता है। तथापि, इस न्यायालय की दो अलग-अलग खण्डपीठों के निर्णयों के बीच विचारों का टकराव था कि एस. बी. कपूर और खन्ना ने *भारत संघ बनाम महाराज,*[18] मामले में कहा है कि इस न्यायालय की दो अलग-अलग खंडपीठों के उचित निर्माण और अर्थ के बारे में निर्णय लिया गया है। जिस अवधि के दौरान कोई कर्मचारी गलत तरीके से बर्खास्तगी के आदेश के तहत था, उस अवधि के लिए बकाया वेतन का बकाया केवल तभी प्राप्त होता है जब सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को एक सक्षम न्यायालय द्वारा रद्द या शून्य घोषित किया जाता है। दूसरी ओर यह *भारत संघ बनाम राम नाथ*[19], में दुलत और एस. के. कपूर, जे.जे. कि जिस अवधि के दौरान वह वास्तव में बर्खास्तगी के आदेश के संचालन के कारण सेवा नहीं कर रहा था, उस अवधि से संबंधित कर्मचारी का वेतन हर महीने के अंत में कर्मचारी को प्राप्त होता रहता है, जब यह घोषित किया जाता है कि बर्खास्तगी का आदेश शून्य था और अस्तित्वहीन माना जाता है - इस संघर्ष को इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा हल किया गया है । और शमशेर बहादुर, जेजे, और मैं, *जगदीश मित्तर बनाम भारत संघ और एक अन्य*[20] में यह माना गया है कि राम, नाथ के मामले का फैसला सही ढंग से किया गया था क्योंकि यह माधव लम्न वैकुंथे के मामले में सुप्रीम कोर्ट के उनके लॉर्डशिप की घोषणा के अनुरूप है। इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के उक्त निर्णय के बाद मैं यह कहूंगा कि **14** मार्च, **1953** से **2** जनवरी, **1956** की अवधि के संबंध में वादी का दावा (मेरे द्वारा संदर्भित दावा 'ए') समय के अनुसार प्रतिबंधित है। हालांकि, वादी 'बी' चिह्नित

16 1957 P.L.R. 173
17 A.I.R. 1962 S.C. 8.
18 R.F.A. 8-D of 1964 decided on 6th September, 1966.
19 I.L.R. (1966) 2 Pb. 907.
20 C.W. 2307 of 1965 decided on 28th February, 1969.

अवधि के लिए अपने दावे का हकदार होगा, यानी 3 जनवरी, 1956 से 4 मार्च, 1958 की अवधि के संबंध में दावा किया जा रहा है।

(14) वादी के वकील ने तब तर्क दिया कि भारतीय रेलवे स्थापना संहिता, खंड एच के नियम 2046 (2) (ए) (जिसे पहले ही इस फैसले के पहले भाग में शब्दशः उद्धृत किया गया है) के आधार पर, वादी को माना जाना चाहिए कि उसे साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, यानी 30 जून तक सेवा में बनाए रखा गया है। 1959, क्योंकि यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि वह उस समय तक कुशल नहीं थे, और उन्हें 55 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने की आवश्यकता वाला कोई आदेश कभी पारित नहीं किया गया था। हम दीवान आत्मा राम की इस दलील से सहमत होने में असमर्थ हैं- इस मामले के तथ्य स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि वादी को 14 मार्च, 1953 को निलंबित कर दिया गया था, और इसलिए, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि 30 जून, 1954 को, जब उन्होंने 55 वर्ष की आयु प्राप्त की, तो उन्हें साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सेवा में बने रहने के लिए पर्याप्त कुशल माना गया था। वादी रेलवे स्थापना संहिता के खंड II के नियम 2046 के उप-नियम (4) के सांविधिक प्रावधानों के कारण सेवा में बना रहा, जिसमें उप-नियम कहा गया है:

> "खंड (1), (2) और (3) में निहित किसी बात के बावजूद, कदाचार के आरोप में निलंबित रेलवे कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख तक पहुंचने पर सेवानिवृत्त होने की आवश्यकता या अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन उसे तब तक सेवा में बनाए रखा जाएगा जब तक कि आरोप की जांच पूरी नहीं हो जाती और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस पर अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाता."

(15) उपरोक्त उद्धृत नियम के संचालन से, वादी को 30 जून, 1954 से 4 मार्च, 1958 तक सेवानिवृत्त होने की अनुमति नहीं थी, जब वादी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही अंततः इस न्यायालय के आदेश में समाप्त हुई, जिसमें उसे उन आरोपों से बरी कर दिया गया, जिन पर उस पर मुकदमा चलाया जा रहा था। चूंकि उनकी सेवा में निरंतरता नियम 2046 (4) के संचालन द्वारा थी, इसलिए उक्त निरंतर सेवा 4 मार्च, 1958 को स्वचालित रूप से समाप्त हो गई। उत्तर रेलवे के मंडल कार्मिक अधिकारी द्वारा 8/23 सितंबर, 1958 को वादी के आवेदन पर 20 जून, 1959 को पारित आदेश 'डी/एल' से भी रेलवे प्राधिकारियों का मन स्पष्ट है, जो आदेश निम्नलिखित भाषा में था:-

> "कृपया ध्यान दें कि बहाली के लिए आपके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि आप 30 जून, 1954 को सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंच गए हैं, और कानूनी रूप से बहाल होने के हकदार नहीं हैं।"

इस प्रश्न में आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी ने अपने वाद के किसी भी हिस्से में विशेष रूप से दावा नहीं किया है कि उसे साठ वर्ष की आयु तक सेवा में रहने वाला माना जाना चाहिए। वह 30 जून, 1959 को साठ वर्ष के हो गए होंगे। उन्होंने 30 जून, 1959 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वेतन का दावा भी नहीं किया है, लेकिन केवल 31 मार्च, 1959 तक ही इसका दावा किया है। यद्यपि आवेदन 3 मार्च, 1959 को दायर किया गया था, मार्च, 1959 के पूरे महीने के वेतन, जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ था, का दावा किया गया था, लेकिन अप्रैल से जून, 1959 के महीनों के लिए कुछ भी दावा नहीं किया गया था। साठ वर्ष की आयु तक के वेतन के लिए ऐसा कोई विशिष्ट दावा वाद में नहीं किया गया है, हम पहली बार अपीलीय स्तर पर इस तरह के दावे को दबाने की अनुमति देने में असमर्थ हैं। इसलिए, भाग (ए) और (सी) द्वारा कवर किए गए वादी का दावा विफल हो जाता है, लेकिन अवधि (बी) के संबंध में उसका दावा सफल होता है।

(16) पूर्वगामी कारणों से, हम आंशिक रूप से इस अपील को स्वीकार करते हैं और ट्रायल कोर्ट के डिक्री को रद्द करते हैं और इसके स्थान पर प्रतिवादी-प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ वादी-अपीलकर्ता के पक्ष में 2,960 रुपये का भुगतान आनुपातिक लागत के साथ करते हैं। यदि इस डिक्री के पारित होने के दो महीने के भीतर अपीलकर्ता को डेक्रेटल राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो यह आज से वास्तविक भुगतान की तारीख तक छह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से भविष्य का ब्याज वहन करेगा।

**न्यायमूर्ति शमशेर बहादुर – सहमत।**

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के समिति उपयोग कि लिए है ताकि यह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। सभी व्यावहारिक और आपराधिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।

हिमांशु आर्य
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
हरियाणा